PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 011
दि. 11.05.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सोमनाथ

सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।
लभते फलं मनोवाञ्छितं मृतः स्वर्गं समाश्रयेत्॥

सोमनाथ
विरासत के 75 साल

"सोमनाथ आशा का वह गीत है जो हमें सिखाता है कि
सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।"
– **श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री** (अध्यक्ष, श्री सोमनाथ ट्रस्ट)

सोमनाथ भारत की अजेय सभ्यता का प्रतीक है। 1000 वर्षों के विनाशकारी प्रहारों के बावजूद,
आज सोमनाथ हमारे आत्म-सम्मान और साहस की जीवंत प्रेरणा बनकर अडिग खड़ा है।

75 वर्ष पहले, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के संकल्प से आधुनिक सोमनाथ का मार्ग प्रशस्त हुआ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह पावन भूमि भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का उद्घोष कर रही है।

आइए, इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बनें

"सरदार साहब के संकल्प से हुए सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष
भारत की अटूट आस्था और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के विजय का महोत्सव है।"
– **श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री**

मुख्य कार्यक्रम

- **माननीय प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो** (सुबह : 9:00 बजे)
- **आध्यात्मिक नाद एवं नृत्य का दिव्य संगम** (सुबह : 9:15 बजे)
- **श्री सोमनाथ का पावन कुंभाभिषेक एवं महापूजा** (सुबह : 9:30 बजे)
- **सूर्य किरण विमानों का अद्भुत एयर-शो** (सुबह : 9:30 बजे)
- **माननीय प्रधानमंत्री की विशाल जनसभा** (सुबह : 10:00 बजे | सद्भावना ग्राउंड)

दिनांक : **11 मई 2026**

स्थान : श्री सोमनाथ मंदिर परिसर, प्रभास पाटन

सोमनाथ की दिव्यता व भव्यता में दें योगदान और बनें गौरवशाली इतिहास का हिस्सा। स्कैन करें।

संपादकीय

चुनावी राजनीति में झालमुड़ी, मछली और जुमलों का नया स्वाद

भारतीय राजनीति का रंग निराला है। यहां कब कौन-सी चीज चुनावी मुद्दा बन जाए और कौन-सा प्रतीक जनता के दिल में उतर जाए, इसका अंदाजा बड़े-बड़े रणनीतिकार भी नहीं लगा पाते। कभी जाति का गणित चलता है, कभी धर्म का, कभी विकास का और कभी राष्ट्रवाद का। लेकिन पश्चिम बंगाल के हालिया राजनीतिक माहौल ने तो जैसे चुनावी विमर्श को ही एक अलग दिशा दे दी। अब चर्चा सड़क, बिजली, पानी या बेरोजगारी की कम और झालमुड़ी, मछली और फुटबॉल की ज्यादा होने लगी। राजनीति में प्रतीकों का महत्व हमेशा से रहा है, मगर इस बार तो दस रुपये की झालमुड़ी को लेकर ऐसा माहौल बना कि मानो उसी ने सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिख दी हो।

वैसे विरोधी दल वर्षों से भाजपा पर धनबल और संसाधनों की ताकत से चुनाव जीतने के आरोप लगाते रहे हैं। कहा जाता रहा कि भाजपा के पास प्रचार का अथाह पैसा है, बड़ी मशीनरी है और चुनावी रणनीति में वह बाकी दलों से बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन बंगाल के चुनावों के बाद व्यंग्यकारों और राजनीतिक गलियारों में यह बात मजाक-मजाक में कही जाने लगी कि भाजपा को जिताने में सबसे बड़ा योगदान किसी अरबपति उद्योगपति का नहीं, बल्कि दस रुपये की झालमुड़ी का रहा। यह सुनने में भले हास्यास्पद लगे, मगर राजनीति में प्रतीक अक्सर वास्तविक मुद्दों से भी ज्यादा असर डालते हैं। झालमुड़ी आखिर है क्या? बंगाल की गलियों में मिलने वाला बेहद सामान्य, सस्ता और लोकप्रिय नाश्ता। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने इसे खाया, तब यह केवल नाश्ता नहीं रहा, बल्कि आम बंगाली संस्कृति से जुड़ने का एक राजनीतिक संदेश बन गया। जनता को यह दिखाने की कोशिश हुई कि देश का सबसे बड़ा नेता भी बंगाल की मिट्टी, स्वाद और संस्कृति से जुड़ सकता है। यही वजह है कि अब व्यंग्य में कहा जा रहा है कि जिस तरह उत्तर भारत की राजनीति में बुलडोजर एक प्रतीक बन गया, वैसे ही बंगाल की राजनीति में झालमुड़ी नया चुनावी प्रतीक बनकर उभरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुलडोजर भारी-भरकम ताकत का प्रतीक माना जाता है, जबकि झालमुड़ी बेहद साधारण और सस्ती चीज है। लेकिन राजनीति में कई बार छोटी चीजें भी बड़े असर छोड़ जाती हैं। ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति में लंबे समय तक शेरनी कहा जाता रहा। उनकी आक्रामक शैली, तेज भाषण और सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की छवि ने उन्हें अलग पहचान दी। मगर चुनावी हार के बाद व्यंग्यात्मक टिप्पणियों में यह तक कहा जाने लगा कि अब दहाड़ नहीं, सिसकियां सुनाई दे रही हैं। राजनीति में जीत और हार दोनों क्षणिक होती हैं, लेकिन जनता और मीडिया का स्वभाव ऐसा है कि वह हर घटना को प्रतीकों और तंज के जरिए याद रखता है। यही कारण है कि बंगाल चुनाव के बाद झालमुड़ी केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यंग्य का हिस्सा बन चुकी है। इसी बीच मछली भी चुनावी चर्चा के केंद्र में आ गई। बंगाल और मछली का रिश्ता सदियों पुराना है। बंगाली भोजन की कल्पना मछली के बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसे में जब नेताओं ने मछली को लेकर बयान देने शुरू किए, तो यह स्वाभाविक था कि वह भी राजनीतिक रंग ले ले। अनुराग ठाकुर के मछली भक्षण की चर्चा हो या रवि किशन का बंगालियों को चार गुना ज्यादा मछली खिलाने का वादा, सब कुछ चुनावी माहौल का हिस्सा बन गया। हालांकि राजनीति में वादों की विश्वसनीयता पर सवाल हमेशा उठते रहे हैं। इसलिए लोगों ने मजाक में यह भी कहना शुरू कर दिया कि कहीं यह वादा भी पंद्रह लाख वाले वादे जैसा जुमला साबित न हो जाए। सबसे दिलचस्प प्रसंग तो हिमंता बिस्वा सरमा और ममता बनर्जी के बीच कथित मछली मुकाबले का रहा। हिमंता ने दावा किया था कि वह ममता दीदी से एक किलो ज्यादा मछली खा सकते हैं। राजनीति में यह दृश्य अपने आप में अनोखा है। कभी नेता सादगी दिखाने की होड़ में रहते थे। कौन ज्यादा साधारण जीवन जीता है, कौन कम खर्च करता है, यही चर्चा होती थी। फिर दौर आया जब नेताओं पर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों की तुलना होने लगी। लेकिन अब राजनीति वहां पहुंच गई है जहां मुकाबला इस बात का होने लगा कि कौन ज्यादा मछली खा सकता है। यह बदलाव भारतीय लोकतंत्र की बदलती शैली को भी दिखाता है, जहां गंभीर मुद्दों के बीच मनोरंजन और तमाशे का तत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "न खाऊंगा, न खाने दूंगा" वाला नारा कभी भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति का बड़ा संदेश माना गया था। मगर अब व्यंग्य यह कहता दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री तो दस रुपये की झालमुड़ी खाकर संतोष कर लेते हैं, जबकि उनके सहयोगी नेता मछली खाने की प्रतियोगिता तक की चुनौती दे रहे हैं। राजनीति में विरोधियों पर तंज कसने का यह तरीका नया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और टीवी बहसों के दौर में यह और भी ज्यादा तीखा और मनोरंजक हो गया है।

टीवीके यानी 'स्टार्टअप' राजनीतिक विकल्प

"टीवीके की सफलता के पीछे नौजवानों की ताकत है, जिसे जेन-ज़ी माना जा रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन सत्ता के खेल को खेलना दूसरी बात है। इन्हें नेताओं की जवाबदेही को भी समझना होगा। समाधान झटपट नहीं मिलते और सिनेमा के नायकों की तरह खासतौर से नहीं।

तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव-परिणामों ने देश में एक नए राजनीतिक 'स्टार्टअप' का नाम जोड़ा है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके का चुनावी पदार्पण बेहद शानदार रहा है। 'स्टार्टअप' शब्द बिजनेस से आया है। तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों को यह नाम दिया जाता है और एक अरब डॉलर से ऊपर का कारोबार करने वाली कंपनी को 'यूनिकॉर्न' कहते हैं। माना जा रहा है कि टीवीके ने रातों-रात भारतीय राजनीति में 'यूनिकॉर्न' बनकर दिखाया है।

तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) ने अपने पहले ही चुनावी मुकाबले के बाद तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), आम आदमी पार्टी (आप), असम गण परिषद (एजीपी) और वाईएसआर कांग्रेस (वाईएसआरसीपी) जैसी पार्टियों के नक्शे-कदम सफलता हासिल की है। वह बेशक पहले ही राउंड में 'यूनीकॉर्न' बनकर उभरी है, पर पर्यवेक्षक मानते हैं कि उसे अभी कठोर परीक्षा से गुजरना होगा। अभी यह सेमीफ़ाइनल जैसा लगता है। शायद साल-दो साल, नई सरकार आए या फिर से चुनाव कराने पड़ें। टीवीके के पीछे नौजवानों की ताकत है, जिसे जेन-ज़ी माना जा रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन सत्ता के खेल को खेलना दूसरी बात है। इस पीढ़ी को घोषणापत्र पढ़ना, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करना या नेताओं की जवाबदेही का मतलब भी समझना होगा। परंपरागत राजनीति में भी युवा ही आगे आते हैं। पर समाधान झटपट नहीं मिलते और सिनेमा को नायकों की तरह खासतौर से नहीं। तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का गहरा संबंध रहा है। अन्नादुरै, एमजीआर, करुणानिधि और जयललिता जैसे सिनेकर्मी अपनी फिल्मी लोकप्रियता के दम पर मुख्यमंत्री बने। पर वे स्पष्ट एजेंडा और दीर्घकालिक रणनीतियों वाले राजनीतिक नेताओं के रूप में परिपक्व हुए। पहली नज़र में लग सकता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, एक और अभिनेता राजनीति में प्रवेश कर रहा है। लेकिन हकीकत में विजय के पीछे युवाओं का अंधाधुंध समर्थन, भोलापन है। राजनीतिक-परिपक्वता नहीं।

राज्य के मतदाता सत्ता-विरोधी लहरों पर सवार हैं। दशकों से वे द्रमुक और अद्रमुक दोनों को रोटेट करके नियंत्रित रखते आए हैं। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में जयललिता के निधन के बाद, नेतृत्व के अभाव और पार्टी की अंदरूनी खींचतान के कारण अन्नाद्रमुक पृष्ठभूमि में चली गई है। इस शून्य के कारण संभवतः टीवीके का उदय हुआ है।

टीवीके संगठित प्रशंसक क्लब है। इसके ज्यादातर कार्यकर्ता विजय के प्रशंसक हैं, जो फिल्मों के रिलीज पर खुशी मनाने के आदी हैं, नीतियों पर बहस करने के नहीं। डीएमके, एआईएडीएमके, सीपीआई, सीपीआई-एम, वीसीके आदि जैसी सभी प्रमुख कार्यकर्ता-आधारित पार्टियों के विपरीत, जो राजनीतिक शिक्षा पर जोर देती हैं।

भारत में राजनीतिक 'स्टार्टअप' को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में रख सकते हैं। एक, किसी आंदोलन से उत्पन्न, दो, किसी पारिवारिक नाम, व्यक्तित्व या वंश के इर्द-गिर्द निर्मित, और तीन, किसी सामाजिक या धार्मिक समूह या विशिष्ट विचारधारा के इर्द-गिर्द विकसित। आंध्र में अस्सी के दशक में एनटी रामाराव के नेतृत्व में तेलुगु देशम को और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काफी सफलता मिली, पर दोनों मौकों पर जनता को विकल्पों की जबर्दस्त जरूरत थी।

वर्ष 1977 में जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ही 'स्टार्टअप' था। 1967 में जब देश में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, तब भी वह विकल्प खोजने का प्रयास था। टीडीपी ने अपने गठन के एक साल बाद, 1983 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और 201 सीटें जीती थीं। एजीपी ने 1985 में अपने गठन के तुरंत बाद असम आंदोलन से जुड़े स्वतंत्र प्रतिनिधियों के समर्थन से सरकार बनाई थी।

1977 में जनता पार्टी ने तो 'यूनिकॉर्न' के रूप में ही शुरुआत की थी, पर वह अपने अंतर्विरोधों को संभाल नहीं पाई और देखते ही देखते अनेक दलों में विभाजित हो गई। बहुत कम राजनीतिक स्टार्टअप 'यूनिकॉर्न' बन पाए हैं। कुछ को समय लगा, जबकि कुछ विफल हो गए। पिछले साल बिहार में जन सुराज पार्टी के साथ ऐसा ही हुआ। अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन की मक्काल नीधि मय्यम भी ऐसी ही एक पार्टी है।

बिहार में पुष्पम प्रिया चौधरी के नेतृत्व वाली प्लूरल्स पार्टी जैसी कई छोटी-छोटी नवगठित पार्टियां हैं। वहीं, जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसी छोटी पार्टियां भी हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं सीमित हैं और वे कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। उ.प्र. में निषाद पार्टी, पीस पार्टी, अपना दल (सोनेलाल) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) जैसी पार्टियां हैं, पर ज्यादातर सीमित जातीय क्षेत्र होने के कारण बड़े स्तर पर जगह नहीं बना पाईं। इस किस्म के प्रयासों की संख्या बहुत बड़ी है।

देश के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो छह राष्ट्रीय पार्टियां हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, मई, 2026 तक इनमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी इस श्रेणी में शामिल हैं। मान्यता चुनावी प्रदर्शन के आधार पर मिली है।

जहां कांग्रेस का उदय स्वतंत्रता आंदोलन से हुआ, वहीं भाजपा, माकपा, बसपा और 'आप' का उदय उनकी राजनीतिक गतिविधियों के सहारे हुआ। एनपीपी मुख्यतः मेघालय की पार्टी है, जिसका गठन पीए संगमा ने 2013 में किया था। टीवीके की तुलना 1982 में आंध्र प्रदेश में उभरी तेलुगु देशम से की जा सकती है, जिसके पीछे फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव की लोकप्रियता थी।

वर्ष 1972 में एमजी रामचंद्रन द्वारा स्थापित अन्ना द्रमुक वस्तुतः द्रमुक से टूटकर उसके ही विकल्प के रूप में बनी थी। एमजीआर के बाद इसे जयललिता जैसा नेतृत्व मिला। इस तथ्य पर भी ध्यान दें कि तमिलनाडु की द्रविड़-राजनीति में सिनेमा के कलाकारों की जबर्दस्त भूमिका रही है।

पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, ओडिशा की बीजू जनता दल और तेलंगाना की एआईएमआईएम जैसी पार्टियां जो क्षेत्रीय स्तर पर शक्तिशाली बनकर उभरी हैं, उन्हें या तो किसी ऐसे जाने-माने राजनीतिक नेता के नेतृत्व में सफलता मिली है, जिन्होंने मूल पार्टी से अलग होकर पार्टी बनाई (ममता बनर्जी), या फिर पारिवारिक साख (नवीन पटनायक और असदुद्दीन ओवैसी) के कारण। हालांकि, एआईएमआईएम का गठन काफी पहले हुआ था, लेकिन ओवैसी के नेतृत्व में इसे लोकप्रियता मिली।

उ.प्र. में समाजवादी पार्टी, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल और कर्नाटक के जनता दल (समाजवादी) के पीछे समाजवाद और जय प्रकाश नारायण के आंदोलनों की पृष्ठभूमि ज़रूर है, पर वे अब पारिवारिक साख पर केंद्रित हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी) जैसी अन्य पार्टियाँ भी कमोबेश ऐसी ही पार्टियां हैं। तमिलनाडु में विदुथलाई चिरुथाइगल काट्ची (वीसीके) दलितों की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन के इर्द-गिर्द बनी थी और तमिलनाडु में इसे सीमित सफलता मिली है। पार्टियों की संख्या बढ़ते जाना, लोकतंत्र में गलत तो नहीं है, पर तब तक निरर्थक है, जब तक उसका कोई वैचारिक अर्थ न हो।

प्रेरणा

समय, संवेदना और समाज का जीवंत काव्य दस्तावेज

हिंदी कविता की परंपरा सदियों से मनुष्य के भीतर और बाहर घटित हो रही घटनाओं को शब्दों में दर्ज करती रही है। हर दौर में कवियों ने अपने समय की परिस्थितियों, सामाजिक बदलावों, मानवीय संबंधों और आत्मिक अनुभवों को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दी है। कविता केवल शब्दों का संयोजन नहीं होती, बल्कि वह मनुष्य की संवेदनाओं, स्मृतियों, संघर्षों और आशाओं का वह दर्पण होती है जिसमें समाज और व्यक्ति दोनों का चेहरा एक साथ दिखाई देता है। यही कारण है कि कविता का प्रभाव हमेशा स्थायी और गहरा रहा है। कुछ कवियों ने अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों को स्वर दिया, तो कुछ ने मनुष्य की आंतरिक यात्रा के उन सूक्ष्म अनुभवों को पकड़ा जो सामान्य जीवन की भागदौड़ में अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। इसी परंपरा में दिलीप कुमार पाण्डेय का नवीन काव्य संग्रह 'मैं समय हूं' एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में सामने आता है। यह काव्य संग्रह केवल कविताओं का संकलन नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर घटित होने वाली संवेदनात्मक यात्राओं का दस्तावेज प्रतीत होता है। संग्रह में शामिल अड़सठ कविताएं जीवन के विविध रंगों, अनुभवों और संघर्षों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है मानो कवि ने केवल समाज को बाहर से नहीं देखा, बल्कि उसे भीतर तक महसूस किया है। यही कारण है कि उनकी कविताएं केवल विचार प्रस्तुत नहीं करतीं, बल्कि पाठक को संवेदनात्मक रूप से जोड़ लेती हैं।

दिलीप कुमार पाण्डेय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी कविताओं में अनावश्यक भावुकता या आक्रोश का सहारा नहीं लेते। आज के समय में जहां बहुत-सी रचनाएं केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया बनकर रह जाती हैं, वहीं उनकी कविताएं गहरे चिंतन और आत्ममंथन से उपजी हुई प्रतीत होती हैं। वे समाज में व्याप्त विसंगतियों को केवल उजागर नहीं करते, बल्कि उन्हें मनुष्य के अनुभव संसार से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि उनकी रचनाएं पाठक को सोचने के लिए विवश करती हैं। 'मैं समय हूं' शीर्षक अपने आप में अत्यंत अर्थपूर्ण है। समय केवल घड़ी की सुइयों का चलना नहीं होता, बल्कि वह मनुष्य के अनुभवों, स्मृतियों, संघर्षों और परिवर्तन का सबसे बड़ा साक्षी होता है। संग्रह की कविता "समय रुकता नहीं" में कवि लिखते हैं — "समय सच है/ अटल भी है/ इधर-उधर मुड़कर नहीं देखता/ अपनी गति से/ निरंतर चलता रहता है।" इन पंक्तियों में केवल समय का दार्शनिक अर्थ ही नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन की वास्तविकता भी छिपी हुई है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह निरंतर बहता रहता है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन की सीमाओं, इच्छाओं और पूर्वनिर्धारित धारणाओं में उलझा रहता है। कवि यहां समय और मनुष्य के बीच के इसी द्वंद्व को अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। संग्रह की कविताओं में रिश्तों की टूटन, सामाजिक असमानता, मनुष्य की अकेलापन भरी यात्रा और स्मृतियों का गहरा असर बार-बार दिखाई देता है। लेकिन इन सबके बीच उम्मीद का एक सूक्ष्म स्वर भी लगातार उपस्थित रहता है। यही इस संग्रह की सबसे बड़ी ताकत है। कवि निराशा को अंतिम सत्य नहीं मानते। वे जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए भी उम्मीद की लौ को बचाए रखते हैं। "मां और माटी" कविता में कवि ने भारतीय जीवन और संवेदना के दो सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों को एक साथ रखा है। मां और माटी केवल शब्द नहीं, बल्कि मनुष्य की जड़ों और उसकी पहचान के प्रतीक हैं। कविता की पंक्तियां — "मां और माटी की/ प्रायः बहस होती है/ नित्य प्रतिदिन/ कहीं दीप जले/ कहीं राग/ तो कहीं संगीत।" इन पंक्तियों में गांव, मिट्टी, संस्कृति और आत्मीयता का पूरा संसार मौजूद है। कवि यहां केवल प्रकृति या रिश्तों का वर्णन नहीं कर रहे, बल्कि वह उस सांस्कृतिक चेतना को शब्द दे रहे हैं जो आधुनिक समय में धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है। दिलीप कुमार पाण्डेय की कविताओं का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका सामाजिक दृष्टिकोण भी है। वे समाज में मौजूद विसंगतियों, विडंबनाओं और टूटते मानवीय संबंधों को गहराई से देखते हैं। लेकिन उनकी दृष्टि केवल आलोचनात्मक नहीं है, बल्कि उसमें संवेदना और मानवीय करुणा भी शामिल है। वे समाज की समस्याओं को बाहर खड़े होकर नहीं देखते, बल्कि स्वयं को उसी समाज का हिस्सा मानकर अभिव्यक्ति देते हैं। यही कारण है कि उनकी कविताओं में कृत्रिमता नहीं दिखाई देती। इस संग्रह की भाषा भी विशेष उल्लेखनीय है। दिलीप कुमार पाण्डेय कठिन शब्दों और जटिल प्रतीकों के माध्यम से पाठक को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करते। उनकी भाषा सहज, सरल और संवादधर्मी है। यही सरलता उनकी कविताओं को अधिक प्रभावशाली बनाती है। उनकी कविताएं पढ़ते समय ऐसा नहीं लगता कि पाठक किसी दुरूह साहित्यिक संसार में प्रवेश कर रहा है, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई संवेदनशील व्यक्ति अपने अनुभव साझा कर रहा हो। संग्रह की कई कविताओं में मनुष्य के भीतर की चुप्पियां बहुत प्रभावशाली ढंग से उभरती हैं। आधुनिक जीवन में संवाद लगातार कम होते जा रहे हैं और मनुष्य भीतर से अधिक अकेला होता जा रहा है। कवि इस अकेलेपन को केवल व्यक्तिगत अनुभव के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे सामाजिक परिस्थिति से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि उनकी कविताएं व्यक्तिगत होते हुए भी सामूहिक अनुभव का रूप ले लेती हैं।

'मैं समय हूं' केवल कविता प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी पाठकों के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है जो साहित्य में जीवन की सच्चाइयों, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ को खोजते हैं। यह संग्रह पाठक को केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सोचने, महसूस करने और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। दिलीप कुमार पाण्डेय ने अपनी कविताओं के माध्यम से यह साबित किया है कि कविता आज भी मनुष्य के भीतर की सबसे गहरी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। समकालीन हिंदी कविता के परिदृश्य में यह संग्रह अपनी संवेदनात्मक गहराई, सामाजिक दृष्टि और आत्मिक अनुभवों की सच्चाई के कारण विशेष महत्व रखता है। यह संग्रह बताता है कि कविता केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन की धड़कनों को सुनने और उन्हें अभिव्यक्ति देने की कला है। दिलीप कुमार पाण्डेय की कविताएं समय, समाज और मनुष्य के रिश्तों को जिस गंभीरता और संवेदनशीलता से प्रस्तुत करती हैं, वह उन्हें समकालीन हिंदी कविता में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है।

धर्मनिरपेक्षता की मृगतृष्णा में भटक रहा 'इंडिया गठबंधन' तोड़ रहा है सियासी दम? जानिए कैसे

धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा मूलतः "सर्वधर्म समभाव" और राज्य की धार्मिक निष्पक्षता पर आधारित रही है। लेकिन पिछले कई दशकों में भारतीय राजनीति के एक हिस्से ने इसे सामाजिक संतुलन के बजाय "अल्पसंख्यक तुष्टिकरण" के राजनीतिक औजार के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि आज अनेक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल वैचारिक संकट से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। सच कहूं तो वे सभी धर्मनिरपेक्षता की मृगतृष्णा में भटक रहे हैं, 'इंडिया गठबंधन' के सहयोगी दल कांग्रेस की बेरुखी से अपना अपना सियासी दम तोड़ते जा रहे हैं! जहां कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक खुद को धर्मनिरपेक्ष राजनीति की केंद्रीय धुरी के रूप में स्थापित रखा। परंतु समय के साथ उस पर यह आरोप मजबूत होता गया कि उसने बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया और वोट बैंक आधारित राजनीति को प्राथमिकता दी। इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा ने "सांस्कृतिक राष्ट्रवाद" और "बहुसंख्यक अस्मिता" के प्रश्न को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया।

आज स्थिति यह है कि जो दल कभी भाजपा के हिंदुत्व विमर्श का तीखा विरोध करते थे, वे भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मंदिर, सनातन परंपरा, जातीय-सामाजिक प्रतिनिधित्व और राष्ट्रवाद की भाषा बोलने लगे हैं। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारतीय मतदाता अब केवल "धर्मनिरपेक्षता" के पारंपरिक नारों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह सांस्कृतिक आत्मसम्मान और विकास के संतुलन की अपेक्षा कर रहा है।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वह अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि उसकी राजनीति की मूल दिशा क्या होगी—पारंपरिक अल्पसंख्यक केंद्रित गठजोड़? सामाजिक न्याय आधारित नई राजनीति? या फिर भारतीय सांस्कृतिक चेतना के साथ सामंजस्य? यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल समय रहते अपने वैचारिक ढांचे का पुनर्मूल्यांकन नहीं करते, तो उनके सामने तीन बड़े खतरे बने रहेंगे—

पहला, बहुसंख्यक समाज से लगातार बढ़ती दूरी उनके लिए सियासी चिंता का सबब बन सकती है। क्योंकि क्षेत्रीय दलों द्वारा उनके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाया जा चुका है। दूसरा, भाजपा के राष्ट्रवादी विमर्श के सामने वैकल्पिक नैरेटिव का अभाव उतपन्न हो गया है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय लोकतंत्र केवल बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक राजनीति पर नहीं चलता। तीसरा, अंततः जनता विकास, सुशासन, सुरक्षा, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आत्मविश्वास—इन सभी का संतुलन चाहती है।

इसलिए भविष्य उसी राजनीतिक शक्ति का होगा जो पहचान की राजनीति से ऊपर उठकर विश्वसनीय शासन मॉडल प्रस्तुत कर सके। कांग्रेस के लिए चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि अपनी वैचारिक प्रासंगिकता बचाने की है। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि वह अपने पुराने ढांचे से बाहर निकलकर नई राजनीतिक भाषा गढ़ पाती है या नहीं।

अभियान

गंगा तट का वह पावन धाम जहां राम ने निभाया मानवता और समानता का धर्म

भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में तीर्थ केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं होते, बल्कि वे हमारी सभ्यता, आस्था, इतिहास और जीवन मूल्यों के जीवंत प्रतीक भी होते हैं। भारत की पावन धरती पर ऐसे अनगिनत तीर्थ हैं जिनकी महिमा हजारों वर्षों से जनमानस के हृदय में बसती आई है। इन्हीं पवित्र स्थलों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक तीर्थ है श्रृंगवेरपुर, जो तीर्थराज प्रयागराज से लगभग पैंतालीस किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह वही स्थान है जहां त्रेतायुग में भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पहुंचे थे। यह केवल रामायण काल की स्मृतियों से जुड़ा स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, भक्ति, प्रेम और लोकमर्यादा का जीवंत संदेश देने वाला पवित्र धाम भी है। श्रृंगवेरपुर का नाम सुनते ही भगवान श्रीराम के वनवास की कथा स्मरण हो उठती है। अयोध्या से वनवास के लिए निकलने के बाद भगवान श्रीराम ने सबसे पहले इसी स्थान पर विश्राम किया था। उस समय यह क्षेत्र निषादराज गुह की राजधानी हुआ करता था। गंगा तट पर बसे इस नगर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत प्राचीन माना जाता है। यहां का वातावरण, गंगा की पावन धारा और रामकथा से जुड़े प्रसंग आज भी श्रद्धालुओं को भावविभोर कर देते हैं। श्रृंगवेरपुर की महिमा केवल भगवान श्रीराम के वनवास तक सीमित नहीं है। इसका संबंध उनके जन्म से भी जोड़ा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ लंबे समय तक संतान सुख से वंचित रहे। अनेक प्रयासों के बाद भी जब उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई, तब कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें श्रृंगी ऋषि के पास जाने का परामर्श दिया। कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि का आश्रम श्रृंगवेरपुर में ही स्थित था। महाराज दशरथ वहां पहुंचे और पुत्र प्राप्ति की कामना व्यक्त की। इसके बाद श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठि यज्ञ का आयोजन कराया। इसी यज्ञ के फलस्वरूप भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार श्रृंगवेरपुर भगवान श्रीराम के जीवन की प्रारंभिक कथा से भी गहराई से जुड़ जाता है। रामचरितमानस और अन्य धार्मिक ग्रंथों में श्रृंगवेरपुर का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन मिलता है। जब भगवान श्रीराम वनवास के लिए निकले तो उनके साथ माता सीता और अनुज लक्ष्मण भी थे। अयोध्या छोड़ने के बाद वे चलते-चलते श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें गंगा नदी पार करनी थी, लेकिन उस समय गंगा अत्यंत वेग से बह रही थी। इसलिए उन्हें वहीं रात्रि विश्राम करना पड़ा। जैसे ही निषादराज गुह को प्रभु श्रीराम के आगमन का समाचार मिला, वे अत्यंत प्रसन्न हुए और फल, फूल तथा अन्य उपहार लेकर प्रभु के स्वागत के लिए पहुंचे। निषादराज ने विनम्रता के साथ भगवान श्रीराम से आग्रह किया कि वे उनके महल में चलकर विश्राम करें। लेकिन भगवान श्रीराम ने वनवासी मर्यादा का पालन करते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसके बाद निषादराज गुह उन्हें एक शांत और सुरक्षित स्थान पर लेकर गए, जिसे आज रामचौरा धाम के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उसी स्थान पर भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण ने रात्रि विश्राम किया था। वहां स्थित शीशम के वृक्ष आज भी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बने हुए हैं। लोग उन वृक्षों की पूजा करते हैं और उनकी परिक्रमा लगाते हैं। यह दृश्य केवल धार्मिक विश्वास का प्रतीक नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है जो पीढ़ियों से भारतीय समाज के भीतर जीवित है। श्रृंगवेरपुर का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग केवट संवाद है, जिसे भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। जब भगवान श्रीराम गंगा पार करने के लिए नाविक को बुलाते हैं, तब केवट तुरंत नाव लेकर नहीं आता। वह प्रभु से विनम्रता के साथ कहता है कि उसने सुना है कि उनके चरणों के स्पर्श से पत्थर भी नारी बन जाते हैं। उसकी नाव तो लकड़ी की बनी है, यदि वह भी स्त्री बन गई तो उसकी जीविका समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह पहले प्रभु के चरण धोना चाहता है। भगवान श्रीराम मुस्कराकर उसकी भावना स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद केवट अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनके चरण धोता है और फिर उन्हें नाव में बैठाकर गंगा नदी पार कराता है। यह प्रसंग केवल भक्ति का चित्रण नहीं करता, बल्कि यह भारतीय समाज को समानता और मानवता का महान संदेश भी देता है। भगवान श्रीराम ने केवट को कभी छोटा या निम्न नहीं माना। उन्होंने प्रेम, सम्मान और आत्मीयता के साथ उसकी भावनाओं को स्वीकार किया। यही कारण है कि यह कथा आज भी समाज में भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक मानी जाती है। श्रृंगवेरपुर के निषाद समाज के लोग स्वयं को उसी केवट का वंशज मानते हैं और बड़े गर्व के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। गंगा पार करने के बाद का प्रसंग भी अत्यंत मार्मिक है। जब भगवान श्रीराम के पास केवट को उतराई देने के लिए कुछ नहीं था, तब माता सीता ने अपनी रत्नजड़ित मुदरी उतारकर प्रभु के हाथों पर रख दी, ताकि उसे केवट को दिया जा सके। लेकिन केवट ने उस मुदरी को लेने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब प्रभु वनवास से लौटकर वापस आएंगे, तब जो कुछ देंगे वह उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करेगा। यह प्रसंग निस्वार्थ सेवा, प्रेम और भक्ति की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करता है। श्रृंगवेरपुर की एक और महत्वपूर्ण कथा माता सीता और मां गंगा से जुड़ी हुई है। गंगा पार करने के बाद माता सीता ने हाथ जोड़कर मां गंगा से प्रार्थना की कि वे उनकी वनवास यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाएं तथा चौदह वर्ष बाद सकुशल अयोध्या लौटने का आशीर्वाद दें। कहा जाता है कि मां गंगा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और वे अपने पति तथा देवर के साथ सुरक्षित अयोध्या लौटेंगी। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां माता सीता ने मां गंगा से प्रत्यक्ष संवाद किया था। यही कारण है कि यह स्थल विशेष रूप से महिलाओं और परिवारों के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है। चौदह वर्ष के वनवास और लंका विजय के बाद जब भगवान श्रीराम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे थे, तब माता सीता ने उन्हें स्मरण कराया कि केवट की उतराई और मां गंगा की पूजा अभी शेष है। इसके बाद भगवान श्रीराम का पुष्पक विमान श्रृंगवेरपुर में उतरा। वहां उन्होंने मां गंगा की पूजा-अर्चना की और निषाद समाज को उपहार प्रदान किए। यह प्रसंग भगवान श्रीराम के आदर्श चरित्र और उनके वचन पालन की भावना को दर्शाता है। उन्होंने वनवास के दौरान बने संबंधों और दिए गए वचनों को कभी नहीं भुलाया। आज भी श्रृंगवेरपुर देशभर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। माघ मेला, कुंभ और महाकुंभ के अवसर पर यहां लाखों लोग आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा और आषाढ़ माह की सप्तमी पर यहां विशाल मेलों का आयोजन होता है। गंगा स्नान, पूजा-अर्चना और रामकथा से जुड़े स्थलों के दर्शन के लिए यहां आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे श्रीराम वनगमन मार्ग ने भी श्रृंगवेरपुर के महत्व को नई पहचान दी है। यह मार्ग उन स्थलों को जोड़ता है जहां-जहां भगवान श्रीराम वनवास के दौरान गए थे। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति और रामायण की परंपराओं से अधिक गहराई से जुड़ सकेगी। श्रृंगवेरपुर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा का प्रतीक है। यहां भगवान श्रीराम और माता सीता ने जिस प्रेम, समानता, करुणा और लोकमर्यादा का संदेश दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना त्रेतायुग में था। यह स्थान हमें सिखाता है कि समाज की वास्तविक शक्ति धन, सत्ता और वैभव में नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और मानवता में निहित होती है। गंगा तट पर स्थित यह पावन धाम आज भी करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धा, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बना हुआ है। यहां पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों की उस गहराई को भी महसूस करता है जिसने इस देश को हजारों वर्षों से एक सूत्र में बांध रखा है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

अब AI बताएगा कब डूबेगा इलाका, कहां बढ़ेगी गर्मी और किस क्षेत्र में होगा खतरा

सूरत। तेजी से विकसित हो रहे सूरत शहर में अब आपदा प्रबंधन व्यवस्था भी पूरी तरह हाई-टेक होने जा रही है। हर साल मानसून के दौरान जलभराव, खाड़ी क्षेत्रों में बाढ़, गर्मियों में बढ़ती हीटवेव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझने वाले शहर के लिए सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित स्मार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। निगम प्रशासन का दावा है कि आने वाले समय में यह तकनीक शहर को प्राकृतिक और पर्यावरणीय संकटों से पहले ही आगाह कर देगी, जिससे राहत और बचाव कार्यों को पहले से अधिक तेज, सटीक और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

इसी दिशा में म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराज की अध्यक्षता में भट्टर स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) में वरिष्ठ अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष वर्कशॉप आयोजित की गई। इस दौरान AI आधारित हाई-टेक डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल पर विस्तृत चर्चा की गई और यह तय किया गया कि भविष्य में सूरत की आपदा प्रबंधन प्रणाली केवल पारंपरिक राहत कार्यों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संभावित खतरे का पहले ही पूर्वानुमान लगाकर समय रहते कार्रवाई करेगी।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार अब तक प्राकृतिक आपदाओं के बाद प्रशासन सक्रिय होता था। भारी बारिश होने के बाद जलभराव वाले क्षेत्रों में पंपिंग मशीनें भेजी जाती थीं, बाढ़ आने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता था और प्रदूषण बढ़ने के बाद कार्रवाई की जाती थी। लेकिन AI आधारित सिस्टम इस पूरी प्रक्रिया को बदल देगा। अब तकनीक पहले ही संकेत दे देगी कि कौन-सा इलाका खतरे में आ सकता है, कहां पानी भरने की संभावना है, किन क्षेत्रों में हीटवेव ज्यादा प्रभाव डाल सकती है और किस इलाके की हवा लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो रही है।

सूरत शहर की सबसे बड़ी समस्या मानसून के दौरान खाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव की रहती है। कई बार भारी बारिश, ऊपरी क्षेत्रों से छोड़े गए पानी और समुद्री ज्वार के एक साथ आने से निचले इलाके जलमग्न

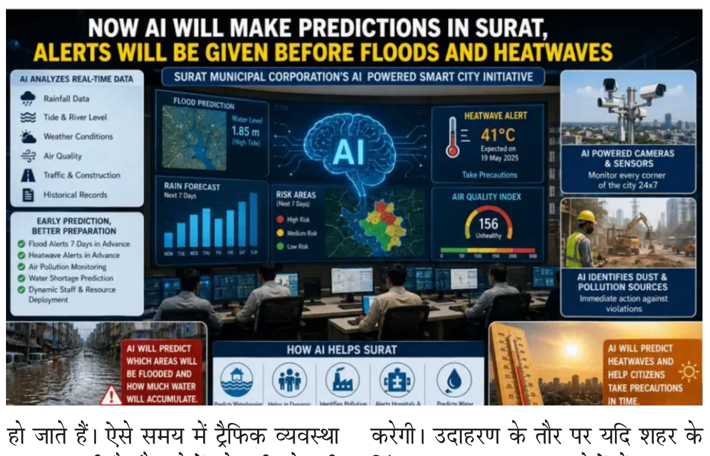

हो जाते हैं। ऐसे समय में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। निगम प्रशासन का कहना है कि नया AI सिस्टम पुराने बारिश के रिकॉर्ड, समुद्री ज्वार के पैटर्न, खाड़ी के जलस्तर और वर्तमान मौसम संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण कर एक सप्ताह पहले ही संभावित खतरे का अनुमान लगा सकेगा। इससे प्रशासन को पहले से तैयारी करने का पर्याप्त समय मिलेगा।

AI तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह रियल-टाइम डेटा पर काम करेगी। उदाहरण के तौर पर यदि शहर के लिंबायत, वराछा या अन्य क्षेत्रों में अचानक अत्यधिक बारिश होती है, तो सिस्टम तुरंत यह विश्लेषण करेगा कि किन इलाकों में पानी भरने की संभावना बढ़ रही है। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि किस क्षेत्र में अतिरिक्त स्टाफ, पंपिंग मशीनें और राहत संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इससे आपात स्थिति में प्रशासन की प्रतिक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और संगठित हो सकेगी।

नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि सूरत जैसे तेजी से बढ़ते शहर में पारंपरिक डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल अब पर्याप्त नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कभी अचानक अत्यधिक बारिश हो रही है, तो कभी गर्मी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रही है। ऐसे में केवल मानवीय अनुमान और पुराने तरीकों के भरोसे आपदा प्रबंधन करना मुश्किल होता जा रहा है। यही कारण है कि अब तकनीक और डेटा आधारित निर्णयों पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

AI सिस्टम केवल बाढ़ या जलभराव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उपयोग प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी किया जाएगा। शहर में लगे स्मार्ट कैमरे और सेंसर लगातार डेटा जुटाएंगे और यह पहचानेंगे कि किन निर्माण स्थलों पर धूल अधिक उड़ रही है, किन औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ रहा है और किन ट्रैफिक जंक्शनों पर कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। इसके आधार पर संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जा सकेंगे।

प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यदि किसी इलाके की वायु गुणवत्ता अचानक अत्यधिक खराब हो जाती है, तो AI सिस्टम स्वतः आसपास के अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल टीमों को अलर्ट भेज देगा। इससे सांस संबंधी बीमारियों, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित मरीजों के लिए पहले से तैयारी की जा सकेगी। नगर निगम का मानना है कि इससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

गर्मी और हीटवेव की चुनौती से निपटने में भी AI तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले कुछ वर्षों में सूरत सहित गुजरात के कई शहरों में तापमान लगातार बढ़ा है। कई क्षेत्रों में गर्मी का असर इतना अधिक होता है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नया सिस्टम शहर के 'हीट हॉटस्पॉट' क्षेत्रों की पहचान करेगा और यह अनुमान लगाएगा कि किन इलाकों में तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि किन क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान पानी की कमी होने की संभावना है। इसके आधार पर जल विभाग पहले से टैंकर, अतिरिक्त जलापूर्ति और अन्य व्यवस्थाओं की योजना तैयार कर सकेगा।

सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले अहमदाबाद मॉडल का भी अध्ययन किया है। अहमदाबाद में AI आधारित डिजास्टर मैनेजमेंट का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहने के बाद अब सूरत प्रशासन भी बड़े स्तर पर इस तकनीक को लागू करने की तैयारी कर रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में विशेषज्ञों की टीम गठित की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर विशेष तकनीकी एजेंसियों को टेंडर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा शहर के मौजूदा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी और अधिक आधुनिक बनाया जाएगा ताकि सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य के स्मार्ट शहरों में AI आधारित डिजास्टर मैनेजमेंट अनिवार्य होता जा रहा है। दुनिया के कई विकसित शहर पहले से ही ऐसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जहां बाढ़, तूफान, हीटवेव और प्रदूषण जैसी समस्याओं का पहले से अनुमान लगाकर जनहानि और आर्थिक नुकसान को कम किया जा रहा है। सूरत में भी इसी दिशा में प्रयास शुरू हो चुके हैं।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि AI तकनीक का उद्देश्य केवल तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यदि शहर में संभावित खतरे की जानकारी पहले ही मिल जाए, तो प्रशासन समय रहते राहत कार्य शुरू कर सकता है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है और आवश्यक संसाधनों की तैनाती की जा सकती है। इससे जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

सूरत लंबे समय से देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शामिल रहा है। टेक्सटाइल, डायमंड और व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ अब शहर स्मार्ट टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रशासन की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। AI आधारित डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को इसी बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले समय में यदि यह परियोजना सफल रहती है, तो सूरत देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो सकता है जहां आपदा प्रबंधन पूरी तरह डेटा, सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित होगा।

वारंगल से शुरू हुई भारत की टेक्सटाइल क्रांति, पीएम मित्रा पार्क से लाखों रोजगार और वैश्विक कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार

नई दिल्ली। भारत के कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने और टेक्सटाइल सेक्टर को आधुनिक औद्योगिक ढांचे से जोड़ने की दिशा में देश ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने रविवार को तेलंगाना के वारंगल में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया। करीब 1,695.54 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह विशाल परियोजना भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है। केंद्र सरकार का दावा है कि यह परियोजना न केवल कपड़ा उद्योग को नई गति देगी बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Warangal में विकसित यह पीएम मित्रा पार्क 1,327 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे एक आधुनिक, एकीकृत तथा विश्वस्तरीय टेक्सटाइल हब के रूप में तैयार किया गया है। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना है और इसकी लगभग 62 प्रतिशत भूमि पहले ही विभिन्न उद्योगों और कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है। इससे यह संकेत मिलता है कि उद्योग जगत में इस परियोजना को लेकर काफी उत्साह है और आने वाले समय में यहां बड़े स्तर पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि वारंगल का पीएम मित्रा पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से वस्त्र निर्माण की समृद्ध परंपरा वाला देश रहा है और अब आधुनिक तकनीक, एकीकृत औद्योगिक ढांचे और बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाओं के माध्यम से देश को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार का उल्लेख करते हुए कहा कि यह परियोजना हजारों महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर पैदा करेगी।

कपड़ा मंत्रालय के अनुसार इस पार्क से सीधे तौर पर 24,400 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से हजारों अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। परियोजना के निर्माण और प्रारंभिक गतिविधियों के दौरान भी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को काम मिला है। सरकार का मानना है कि इस प्रकार की परियोजनाएं केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करती हैं।

पीएम मित्रा योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इसके तहत देश के सात राज्यों — तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश — में एक-एक मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इन पार्कों को आधुनिक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां कपड़ा उद्योग की पूरी मूल्य श्रृंखला एक ही परिसर में उपलब्ध होगी।

अहमदाबाद मण्डल के रेल के कर्मचारियों ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, यात्री की खोई हुई सोने की अंगूठी खोजकर लौटाई

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल के रेल के कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से मानवता का परिचय दिया है। इसी क्रम में गाड़ी संख्या 09037 बांद्रा टर्मिनस-भुज स्पेशल के कोच संख्या B8 में यात्रा कर रहे एक यात्री की सोने की अंगूठी अचानक टॉयलेट के ड्रेनेज में गिर गई, जिससे यात्री अत्यंत चिंतित और परेशान हो गए थे। जैसे ही ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पहुँची। श्री संजय यादव, सीनियर सेक्शन इंजीनियर (C&W) और अन्य सुपरवाइजरों और CTS (क्लीन ट्रेन स्टेशन) स्टाफ श्री वीरेंद्र कुमार सिंह ने तुरंत जिम्मेदारी संभाली।

पाइपलाइन और गंदगी के बीच से छोटी सी अंगूठी को ढूंढना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन रेलवे की इस टीम ने हार नहीं मानी। काफी मेहनत, धैर्य और अथक प्रयास के बाद, टीम ने सफलतापूर्वक उस सोने की अंगूठी को खोज निकाला। यह कार्य केवल अपनी ड्यूटी निभाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह रेल कर्मचारियों की संवेदनशीलता और यात्री के विश्वास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

श्री संजय यादव और श्री वीरेंद्र कुमार सिंह की इस ईमानदारी और तत्परता ने न केवल एक यात्री की कीमती अमानत को सुरक्षित वापस लौटाया, बल्कि समाज में भारतीय रेल की छवि को भी और अधिक गौरवान्वित किया है।

मजबूत मांग के दम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज का बड़ा दांव, 39 हजार करोड़ रुपये की बिक्री का रखा लक्ष्य

नई दिल्ली। देश के रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार बढ़ती मांग और ब्रांडेड डेवलपर्स पर ग्राहकों के बढ़ते भरोसे के बीच गोदरेज प्रॉपर्टीज ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आक्रामक विस्तार रणनीति अपनाई है। कंपनी ने इस वित्त वर्ष में अपनी बिक्री बुकिंग को करीब 14 प्रतिशत बढ़ाकर 39,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। कंपनी प्रबंधन का मानना है कि आवासीय बाजार में बनी मजबूत मांग और संगठित डेवलपर्स की ओर ग्राहकों का बढ़ता रुझान आने वाले समय में भी कंपनी की वृद्धि को गति देता रहेगा।

कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन पिरोजशा गोदरेज ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भले ही कई तरह की आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी हुई हों, लेकिन भारतीय आवासीय बाजार की बुनियादी स्थिति मजबूत बनी हुई है। उन्होंने संकेत दिया कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव पर कंपनी लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल उसे अपने विकास लक्ष्यों को हासिल करने में किसी बड़ी चुनौती की आशंका नहीं दिख रही।

उन्होंने कहा कि भारतीय रियल एस्टेट बाजार में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ग्राहक अब छोटे और असंगठित डेवलपर्स की तुलना में भरोसेमंद, पारदर्शी और समय पर परियोजनाएं पूरी करने वाले बड़े ब्रांडेड डेवलपर्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका सीधा लाभ गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसी कंपनियों को मिल रहा है, जिन्होंने गुणवत्ता, विश्वसनीयता और समयबद्ध डिलीवरी के आधार पर बाजार में मजबूत पहचान बनाई है।

Godrej Properties ने पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 34,171 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग दर्ज की थी। यह कंपनी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। खास बात यह है कि कुछ वर्षों पहले यानी वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी की बिक्री बुकिंग केवल 6,725 करोड़ रुपये थी। इस तरह पांच वर्षों के भीतर कंपनी ने अपने कारोबार में कई गुना वृद्धि दर्ज की है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि और घर खरीदने की बढ़ती मानसिकता ने संगठित रियल एस्टेट कंपनियों को मजबूत आधार प्रदान किया है।

पिरोजशा गोदरेज ने बताया कि मार्च महीने में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं का असर कुछ समय के लिए ग्राहकों की खरीदारी गतिविधियों पर दिखाई दिया था। हालांकि अप्रैल से स्थिति में सुधार आया और बिक्री की गति फिर सामान्य हो गई। उन्होंने कहा कि कंपनी को आने वाले महीनों में आवासीय मांग में और मजबूती की उम्मीद है।

कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में ग्राहकों से 24,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य भी तय किया है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने ग्राहकों से 19,965 करोड़ रुपये का संग्रह किया था। यह बढ़ोतरी बताती है कि कंपनी केवल नई बिक्री पर ही नहीं बल्कि नकदी प्रवाह को मजबूत रखने पर भी फोकस कर रही है। मजबूत कैश फ्लो किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और विस्तार योजनाओं को गति देने में मदद मिलती है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने नए भूखंडों और परियोजनाओं के अधिग्रहण की रणनीति पर भी आक्रामक रुख बनाए रखा है। कंपनी का कहना है कि वह ऐसी परियोजनाओं को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहती है जिनसे लगभग 20,000 करोड़ रुपये का संभावित राजस्व हासिल किया जा सके। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 18 नए भूखंडों का अधिग्रहण किया था, जिनकी अनुमानित राजस्व क्षमता करीब 42,100 करोड़ रुपये आंकी गई है। इससे स्पष्ट है कि कंपनी केवल मौजूदा परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि भविष्य की मांग को देखते हुए अपने भूमि बैंक और प्रोजेक्ट पाइपलाइन को लगातार मजबूत कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के सनातन रामधाम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागी हुए

मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित श्री राम दरबार तथा अन्य मूर्तियों के दर्शन कर राज्य के नागरिकों की सुख-समृद्धि के लिए मंगलकामनाएँ कीं

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल रविवार को अहमदाबाद में थलतेज स्थित श्री सनातन रामधाम मंदिर में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल श्री राम दरबार तथा अन्य मूर्तियों के दर्शन-पूजन कर महाआरती में सहभागी हुए और उन्होंने राज्य के नागरिकों की सुख-समृद्धि के लिए मंगलकामनाएँ कीं। महोत्सव में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नीतिनभाई पटेल भी उपस्थित रहे।

लगभग 90 वर्ष पुराने इस मंदिर का गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड तथा अन्य दाताओं के सहयोग से जीर्णोद्धार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने इस मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के 10 दिवसीय महोत्सव के अंतिम दिन रविवार को उपस्थित रहकर भक्ति एवं सनातन संस्कारों के अविरत केंद्र समान रामधाम मंदिर में दर्शन कर धन्यता की अनुभूति की।

श्री भूपेंद्र पटेल मंदिर के गर्भगृह में शास्त्रोक्त विधि-विधान तथा मंत्रोच्चार के साथ आयोजित पूजा विधि में सहभागी हुए। इस अवसर पर 'जय श्री राम' तथा 'श्री रामधुन' से समग्र वातावरण भक्तिमय बन गया।

जिंदगी बचाने वाली एम्बुलेंस बनी मौत का कारण, ऑक्सीजन खत्म होने पर युवक ने रास्ते में तोड़ा दम

पाली। राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पाली जिले के सबसे बड़े सरकारी बांगड़ अस्पताल से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने चिकित्सा व्यवस्थाओं की संवेदनशीलता और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों पर बहस छेड़ दी है। 108 एम्बुलेंस, जिसे आमतौर पर मरीजों की जिंदगी बचाने वाली सेवा माना जाता है, वही एक परिवार के लिए मौत का कारण बन गई। आरोप है कि जोधपुर रेफर किए गए एक 20 वर्षीय युवक की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण रास्ते में ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन, एम्बुलेंस स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।

मृतक युवक की पहचान पाली के नया गांव सांसी बस्ती निवासी सावन कुमार के रूप में हुई है। सावन पिछले करीब छह महीने से गंभीर किडनी रोग से जूझ रहा था। उसकी हालत लगातार खराब बनी हुई थी और सप्ताह में दो बार उसका डायलिसिस कराया जाता था। परिवार के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद वे लगातार उसका इलाज कराने की कोशिश कर रहे थे। चार दिन पहले अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर सावन को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसे आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन रविवार को उसकी हालत और गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर कर दिया।

परिजनों का कहना है कि रेफर किए जाने के बाद उन्हें भरोसा था कि 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए सावन को सुरक्षित जोधपुर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन रास्ते में जो हुआ उसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। परिवार का आरोप है कि एम्बुलेंस में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर बीच रास्ते में खत्म हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन सपोर्ट बंद हुआ, सावन की सांसें तेज चलने लगीं और उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। मृतक के भाई देवाराम ने बताया कि उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस चालक और स्टाफ को इसकी जानकारी दी, लेकिन समय रहते दूसरा सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

परिजनों के अनुसार चालक ने दूसरा सिलेंडर लगाने या इंतजाम करने की बात कही, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एम्बुलेंस जब ओम बन्ना क्षेत्र के पास पहुंची, तभी सावन ने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि यदि एम्बुलेंस में पर्याप्त ऑक्सीजन व्यवस्था होती और समय पर दूसरा सिलेंडर लगाया जाता तो शायद सावन की जान बचाई जा सकती थी। इस घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां लाली देवी बेसुध हो गईं। अस्पताल पहुंचे परिजन और समाज के लोग भी गहरे आक्रोश में दिखाई दिए। शव को वापस बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। गुस्साए परिजनों और समाज के लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि जब गंभीर मरीज को रेफर किया जाता है तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, जरूरी दवाएं और अन्य जीवन रक्षक सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध होनी चाहिए। यदि रास्ते में ही ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो यह सीधी लापरवाही मानी जानी चाहिए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर मामले की जांच का भरोसा दिलाया। इसके बाद स्थिति कुछ शांत हुई। हालांकि परिजन इस मामले में जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग पर अड़े रहे। इस घटना ने एक बार फिर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को सामने ला दिया है। सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं उन दावों की पोल खोल देती हैं। खासकर 108 एम्बुलेंस सेवा को ग्रामीण और गरीब मरीजों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। ऐसे में यदि उसी सेवा में ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सुविधा की कमी सामने आए तो यह बेहद गंभीर मामला बन जाता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब बांगड़ अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी यहां इलाज में लापरवाही, संसाधनों की कमी और मरीजों को समय पर सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायतें सामने आती रही हैं। लेकिन हर बार जांच और कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया होता तो आज एक युवा की जान नहीं जाती।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि गंभीर मरीजों को रेफर करते समय एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट की पर्याप्त व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। विशेष रूप से उन मरीजों के लिए जो आईसीयू से रेफर किए जाते हैं। ऐसे मामलों में एम्बुलेंस स्टाफ की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि मरीज की जिंदगी पूरी तरह रास्ते में मिलने वाली चिकित्सा सहायता पर निर्भर होती है। यदि ऑक्सीजन सपोर्ट अचानक बंद हो जाए तो कुछ ही मिनटों में स्थिति जानलेवा हो सकती है।

घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से भी पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर की स्थिति क्या थी और रास्ते में आखिर ऑक्सीजन सपोर्ट क्यों बंद हुआ। वहीं परिजनों का कहना है कि मामले की केवल औपचारिक जांच नहीं बल्कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े। इस दर्दनाक घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही तय कब होगी। एक ओर सरकार आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं के विस्तार की बात करती है, दूसरी ओर जमीनी स्तर पर बुनियादी व्यवस्थाओं की कमी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। सावन कुमार की मौत केवल एक परिवार की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि उस स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है जहां कभी-कभी छोटी सी लापरवाही भी जिंदगी और मौत के बीच फर्क बन जाती है। पाली की इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि जिले की सभी एम्बुलेंस सेवाओं की जांच कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर वाहन में पर्याप्त ऑक्सीजन, जरूरी उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद हो। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो ऐसी घटनाएं भविष्य में भी दोहराई जा सकती हैं। फिलहाल सावन कुमार की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर एक युवा की जान बचाई जा सकती थी तो फिर व्यवस्था क्यों नाकाम साबित हुई।

पश्चिम रेलवे-रतलाम मंडल
ई-निविदा सूचना
Tender Notice No. M247GTWDETC 1710 262708 Dated 07.05.2026. **1. कार्य का नाम:** 8 व्हीलर DETC (सिंगल इंजन प्रकार - 1710) के डीजल अल्टरनेटर सेट एवं अन्य संबद्ध उपकरणों का ओवरहॉलिंग कार्य। मात्रा - **05 नग DETC. Location:** Office of CWM / Dahod W.Rly. मु. का. प्र. / दाहोद प. रेलवे कार्यालय. **2. कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 3,34,89,275/- 3. बयाना राशि: ₹ 6,69,800/- 4. ई-निविदा जमा करने तथा खुलने की दिनांक तथा समय:** ई-निविदा जमा करने की नियत दिनांक तथा समय 29.05.2026 को 14.30 बजे तक तथा ई-निविदा उसी दिन 15.00 बजे खोली जायेगी। **5.** The Tender Notice and documents available on the website **www.ireps.gov.in** / E-Tenders / Works / IR Electrical. CRY/IND/43
हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे-रतलाम मंडल
ई-निविदा सूचना
क्र. सं. 1) ई टेंडरिंग संख्या: EL-2025-26-45R. कार्य का नाम: Ratlam Division - Upgradation of station including circulating area, water supply and approach roads at Ujjain, Laxmibai nagar and Naikheri (Simhastha 2028). **अनुमानित लागत:** ₹ 10320570.13 **बयाना राशी:** ₹ 206400.00 **कार्य की समापन अवधि:** 12 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि:** 05/05/2026. **निविदा खुलने की तिथि:** 02/06/2026. **क्र. सं. 2) ई टेंडरिंग संख्या: EL-2026-27-06. कार्य का नाम:** Ratlam - Electrical work in connection with repair to toilet blocks at DRM Office & TRD Building campus, provision of officers Toilet block near account section at DRM Office. **अनुमानित लागत:** ₹ 302211.42 **बयाना राशी:** ₹ 6100.00 **कार्य की समापन अवधि:** 09 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि:** 05/05/2026. **निविदा खुलने की तिथि:** 02/06/2026. CRY/IND/44
हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे-रतलाम मंडल
ई-निविदा सूचना
निविदा संख्या: SnT-RTM - 26- Tele- 09 दिनांक: 04.05.2026. निम्न कार्य के लिए मंडल रेल प्रबंधक (संकेत एवं दूरसंचार), पश्चिम रेलवे, रतलाम द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **कार्य का नाम:** सिंहस्थ- 2028 के संबंध में रतलाम मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के उन्नयन एवं प्रतिस्थापन हेतु आईपीआईएस (इंटीग्रेटेड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम) सहित संबंधित दूरसंचार उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग। **कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 3,83,95,637.16/- निविदा प्रपत्र का मूल्य:** शून्य. **जमानत राशि: 7,67,900/- कार्य पूर्ण करने की अवधि:** नौ (09) माह. **ई-निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि व समय:** दिनांक 08/06/2026 समय 15.00 बजे तक। **ई-निविदा खोलने की तिथि व समय:** दिनांक 08/06/2026 समय 15.30 बजे तक। **वैधता:** निविदा खुलने की दिनांक से 60 दिन। निविदा **http://www.ireps.gov.in** वेबसाइट पर देखी जा सकती है। निविदाकार के पास Class-III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है तथा IREPS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। केवल पंजीकृत निविदाकार ही ई-टेंडरिंग में भाग ले सकते हैं। CRY/IND/37
हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे-रतलाम मंडल
ई-निविदा सूचना
मंडल रेल प्रबंधक /मंडल कार्यालय (कार्य लेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए "खुली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेबसाईट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है। **क्र. सं. 1) ई टेंडरिंग संख्या: RTM-2025-26-164R1. कार्य का नाम:** Execution of Work in RTM Division - (Composite Work -Civil + Electrical) 1. Ratlam Division - Civil Work in C/with Upgradation and Replacement of Telecom Passenger Amenities at 09 Stations (Simhastha 2028) 2. Ujjain - Civil Work in C/with Upgradation and Replacement of Telecom Passenger Amenities and Various Facilities in Connection of Simhastha 2028. **अनुमानित लागत: ₹ 1,70,77,184.77 बयाना राशी: ₹ 3,41,600.00 कार्य की समापन अवधि:** 10 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि:** 04.05.2026. **निविदा खुलने की तिथि:** 29.05.2026. **क्र. सं. 2) ई टेंडरिंग संख्या: RTM-2026-27-28. कार्य का नाम:** Baranagar Station - Raising of Platform No. 2 (MEA). **अनुमानित लागत: ₹ 2,06,89,530.74 बयाना राशी: ₹ 4,13,800.00 कार्य की समापन अवधि:** 8 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि:** 04.05.2026. **निविदा खुलने की तिथि:** 29.05.2026. **क्र. सं. 3) ई टेंडरिंग संख्या: RTM-2026-27-29. कार्य का नाम:** Ratlam Maintenance of Garden , green patches of station, DRM Office, Divisional Hospital and Colony Bunglows lawn/green patches in Railway Premises for two years (2024-26) Balance Work. **अनुमानित लागत: ₹ 21,21,727.46 बयाना राशी: ₹ 42,400.00 कार्य की समापन अवधि:** 13 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि:** 04.05.2026. **निविदा खुलने की तिथि:** 29.05.2026. **क्र. सं. 4) ई टेंडरिंग संख्या: RTM-2026-27-30. कार्य का नाम:** Ratlam-Annual Maintenance and cleaning of underground sewer line, drain, manholes, inspection chamber, gully trap, sewer line in railway premises, D Shed, Station for three years (2026-29). **अनुमानित लागत: ₹ 51,44,475.32 बयाना राशी: ₹ 1,02,900.00 कार्य की समापन अवधि:** 36 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि:** 04.05.2026. **निविदा खुलने की तिथि:** 29.05.2026. विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य शर्तें वेब साईट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। CRY/IND/41
हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly

खाड़ी में तेल संकट गहराया: अमेरिकी घेराबंदी के बीच समुद्र में कच्चा तेल बहाने की आशंका से बढ़ी वैश्विक चिंता

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच अब एक नया और गंभीर संकट उभरता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और इजरायल के साथ जारी टकराव के बीच ईरान पर बढ़ती समुद्री घेराबंदी का असर अब उसके तेल उद्योग पर साफ दिखाई देने लगा है। हालात इतने गंभीर बताए जा रहे हैं कि ईरान के सामने तेल भंडारण का अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में फारस की खाड़ी के कई हिस्सों, खासकर खार्ग द्वीप के आसपास समुद्र की सतह पर फैले बड़े काले धब्बे दिखाई देने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आशंका जताई जा रही है कि अतिरिक्त कच्चा तेल समुद्र में छोड़ा जा रहा है। यदि यह आशंका सही साबित होती है तो इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था और समुद्री पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

Iran लंबे समय से दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर निर्भर करता है। प्रतिदिन 30 लाख बैरल से अधिक कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला ईरान मुख्य रूप से फारस की खाड़ी में स्थित Kharg Island टर्मिनल के जरिए तेल निर्यात करता है। लेकिन हाल के महीनों में अमेरिकी नौसेना की बढ़ती निगरानी, समुद्री नाकेबंदी और प्रतिबंधों ने तेल टैंकरों की आवाजाही को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के समुद्री मार्गों में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण कई तेल टैंकर खाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

इस स्थिति ने ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर दी है — उत्पादन जारी रहे या तेल कुओं को बंद किया जाए। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि तेल उत्पादन अचानक रोकना ईरान के लिए बेहद जोखिम भरा कदम हो सकता है। कई तेल कुओं में लंबे समय तक उत्पादन बंद रहने से भूमिगत दबाव प्रणाली और संरचना को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। यही कारण है कि उत्पादन पूरी तरह रोकने के बजाय ईरान स्टोरेज के वैकल्पिक रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में अमेरिकी दबाव और समुद्री निगरानी बढ़ने के बाद ईरान के ऑनशोर स्टोरेज टैंक लगभग भर गए। इसके बाद पुराने तेल टैंकरों को समुद्र में फ्लोटिंग स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन अब वह क्षमता भी सीमित होती दिखाई दे रही है। इसी बीच यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सेंटिनल सैटेलाइट डेटा और अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में खार्ग द्वीप तथा फारस की खाड़ी के अन्य हिस्सों के आसपास समुद्र में बड़े काले धब्बे दिखाई दिए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार 6 मई को खार्ग द्वीप के पश्चिम में लगभग 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र की सतह पर एक विशाल तेल जैसी परत देखी गई। इससे पहले लावन द्वीप, केशम द्वीप और कुवैत तट के आसपास भी ऐसे संकेत मिले थे। सैटेलाइट तस्वीरों में समुद्र की सतह पर दिखाई देने वाले ये काले हिस्से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब समुद्र की सतह पर तेल फैलता है तो वह लहरों की प्राकृतिक गतिविधि को प्रभावित करता है, जिससे रडार आधारित सैटेलाइट इमेज में चिकने और गहरे रंग के क्षेत्र दिखाई देते हैं।

हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर पूरी तरह यह कहना संभव नहीं है कि ये धब्बे निश्चित रूप से कच्चे तेल के ही हैं। लेकिन मौजूदा हालात, स्टोरेज संकट और बढ़ती समुद्री नाकेबंदी को देखते हुए आशंकाएं मजबूत होती जा रही हैं कि अतिरिक्त तेल समुद्र में छोड़ा जा रहा हो सकता है। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका सबसे गंभीर असर पर्यावरण पर पड़ेगा। फारस की खाड़ी दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक मानी जाती है। यहां बड़ी संख्या में समुद्री जीव, कोरल रीफ, मछलियां और समुद्री वनस्पतियां पाई जाती हैं। समुद्र में बड़े पैमाने पर तेल फैलने से ऑक्सीजन संतुलन प्रभावित होता है और समुद्री जीवन पर विनाशकारी असर पड़ सकता है। हाल ही में ओमान के धोफार क्षेत्र में बड़ी संख्या में मृत झींगे मिलने की घटनाओं ने भी पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है।

ऊर्जा बाजार पर भी इस संकट का असर दिखाई देने लगा है। Strait of Hormuz दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग माना जाता है। वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यदि यहां तनाव और बढ़ता है या समुद्री परिवहन और बाधित होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। इसका सीधा असर भारत जैसे तेल आयातक देशों पर पड़ेगा, जहां पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा लागत बढ़ने की आशंका बढ़ जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान खुले समुद्री निर्यात में आई बाधाओं के बावजूद गुप्त नेटवर्क के जरिए तेल बेचने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के पास समुद्र में जहाज से जहाज तेल ट्रांसफर कर चीन तक सप्लाई पहुंचाई जा रही है। अमेरिकी एजेंसियों का अनुमान है कि इस तरीके से करीब 2.2 करोड़ बैरल तेल ट्रांसफर किया गया। यह नेटवर्क कथित तौर पर ऐसे पुराने टैंकरों का इस्तेमाल करता है जो ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके समुद्र में तेल ट्रांसफर करते हैं। China लंबे समय से ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका लगातार उन शिपिंग नेटवर्क और कंपनियों पर कार्रवाई कर रहा है जो ईरानी तेल व्यापार में शामिल बताए जाते हैं।

दूसरी ओर ईरानी अधिकारियों ने अभी तक सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दिए तेल के धब्बों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में समुद्र में तेल की परतें और बढ़ती दिखाई देती हैं तो यह वैश्विक स्तर पर बड़ा पर्यावरणीय और राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब केवल सैन्य और राजनीतिक टकराव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता पर भी पड़ने लगा है। यदि ईरान पर दबाव और बढ़ता है तथा तेल निर्यात पूरी तरह बाधित होता है, तो दुनिया को एक नए ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है।

भारत सहित कई एशियाई देशों के लिए यह स्थिति विशेष चिंता का विषय है क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर करता है। ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार की अस्थिरता वैश्विक बाजारों में भारी उथल-पुथल पैदा कर सकती है।

फिलहाल दुनिया की नजरें फारस की खाड़ी पर टिकी हैं, जहां समुद्र की सतह पर दिखाई दे रहे काले धब्बे केवल तेल संकट का संकेत नहीं, बल्कि उस बड़े भू-राजनीतिक संघर्ष की चेतावनी भी माने जा रहे हैं, जिसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर पड़ सकता है।

अब 18 साल के बाद भी नहीं टूटेगा सहारा, अनाथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिल्ली सरकार लाई नई आफ्टरकेयर योजना

नई दिल्ली। अनाथ और संस्थागत देखभाल में पले-बढ़े युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अक्सर देखा जाता है कि चाइल्ड केयर संस्थानों में रहने वाले बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक तो संरक्षण, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जैसे ही वे बालिग होते हैं, उनके सामने जिंदगी की सबसे कठिन चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। परिवार का सहारा न होने, आर्थिक संसाधनों की कमी और सामाजिक असुरक्षा के कारण कई युवा पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं या फिर अस्थिर जीवन की ओर धकेल दिए जाते हैं। इसी संवेदनशील समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 'आफ्टरकेयर स्कीम फॉर यंग पर्सन्स' नामक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने मातृ दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बच्चों को आश्रय देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाना है। उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा संस्थागत देखभाल से बाहर निकलता है, तब असली चुनौती शुरू होती है। ऐसे युवाओं को केवल आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि भावनात्मक सहारा, मार्गदर्शन और अवसरों की भी जरूरत होती है। सरकार इसी सोच के साथ इस योजना को लागू कर रही है ताकि कोई भी युवा 18 वर्ष की उम्र के बाद खुद को असहाय और अकेला महसूस न करे।

दिल्ली में वर्तमान समय में 88 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस संचालित हैं, जहां अनाथ, परित्यक्त और जरूरतमंद बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन संस्थानों में बच्चों की देखभाल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत की जाती है। लेकिन कानून के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद युवाओं को संस्थानों से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में जिन युवाओं के पास परिवार का सहारा या सुरक्षित सामाजिक वातावरण नहीं होता, उनके लिए आगे की जिंदगी बेहद कठिन हो जाती है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष लगभग 150 से 200 युवा चाइल्ड केयर संस्थानों से बाहर आते हैं। इनमें से कई युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ रोजगार की तलाश में होते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें मानसिक और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। अब तक इन युवाओं के लिए व्यवस्थित आफ्टरकेयर सपोर्ट का अभाव था, जिसके कारण कई प्रतिभाशाली युवा अवसरों से वंचित रह जाते थे। नई योजना इसी कमी को दूर करने का प्रयास मानी जा रही है।

सरकार के अनुसार नई आफ्टरकेयर योजना के तहत युवाओं को बहुआयामी सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें उच्च शिक्षा और कॉलेज अध्ययन में मदद, स्किल डेवलपमेंट और व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर, मासिक स्टाइपेंड, करियर गाइडेंस, मेंटरिंग, काउंसलिंग और भावनात्मक सहयोग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसके अलावा स्वतंत्र जीवन की तैयारी, पुनर्वास और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि संस्थागत देखभाल में पले-बढ़े युवाओं के सामने केवल आर्थिक चुनौतियां ही नहीं होतीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक असुरक्षा भी बड़ी समस्या होती है। कई युवाओं को परिवार जैसा समर्थन नहीं मिल पाता, जिससे वे आत्मविश्वास की कमी और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। ऐसे में यदि सरकार केवल वित्तीय सहायता तक सीमित न रहकर मेंटरिंग और भावनात्मक सहयोग भी उपलब्ध कराती है, तो यह योजना वास्तव में युवाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। दिल्ली सरकार ने योजना के प्रभावी संचालन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 3.5 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। सरकार का कहना है कि हर पात्र युवा की व्यक्तिगत जरूरतों का आकलन कर उसके लिए अलग-अलग 'इंडिविजुअल केयर प्लान' तैयार किया जाएगा। यानी प्रत्येक युवा की शिक्षा, रोजगार, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल से जुड़ी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायता दी जाएगी।

योजना की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था भी बनाई जा रही है। राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में स्टेट आफ्टरकेयर कमेटी गठित की जाएगी। वहीं जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट आफ्टरकेयर कमेटियां बनाई जाएंगी। ये समितियां युवाओं की जरूरतों का आकलन करेंगी, उन्हें उपयुक्त सहायता उपलब्ध कराएंगी और समय-समय पर उनकी प्रगति की निगरानी भी करेंगी।

मातृ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने Village Cottage Home पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर बच्चे को सुरक्षा, अपनापन और आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समाज की संवेदनशीलता का सबसे बड़ा पैमाना यह होता है कि वह अपने सबसे कमजोर और जरूरतमंद बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है।

बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी; सम्राट चौधरी सरकार ने बदला सत्ता-प्रबंधन का समीकरण

पटना। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य सरकार ने रविवार (10 मई) को कई वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यह फेरबदल केवल रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राज्य के शासन-प्रबंधन ढांचे को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।

मुख्यमंत्री Samrat Choudhary के नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रशासनिक पुनर्गठन के जरिए कई महत्वपूर्ण विभागों में नई ऊर्जा और कार्यक्षमता लाने का प्रयास किया है। तबादलों की इस सूची में कई ऐसे अधिकारी शामिल हैं जिन्हें या तो नई जिम्मेदारियां दी गई हैं या फिर अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर से वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार वापस लिया जाना शामिल है। यह निर्णय प्रशासनिक संतुलन और विभागीय कार्यभार को अधिक सुव्यवस्थित करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। इसी क्रम में एचआर श्रीनिवास को समाज कल्याण विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। यह नियुक्ति सामाजिक न्याय और कल्याण योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। संतोष कुमार मल्ल को आपदा प्रबंधन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग और विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थानिक आयुक्त कार्यालय) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य में प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पूर्व सचिव लोकेश कुमार सिंह को स्थानांतरित कर पर्यटन विभाग का सचिव बनाया गया है। उन्हें विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इस बदलाव को प्रशासनिक अनुभव के बेहतर उपयोग की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है, जिससे पर्यटन और तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नई गति मिल सकती है।

एक और अहम बदलाव में कुंदन कुमार को स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन (नई दिल्ली) और निवेश आयुक्त (मुंबई) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वहीं कुमार रवि को सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय से स्थानांतरित कर स्वास्थ्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और संसदीय समन्वय दोनों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य विभाग में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि राज्य की चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

मदर्स डे पर मातम: रसोई में लगी आग ने छीन ली मां और दो मासूम बेटियों की जिंदगी, जिंदा जलकर तीनों की दर्दनाक मौत

जयपुर/ब्यावर। राजस्थान के ब्यावर जिले से मदर्स डे के दिन एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। जिस दिन दुनिया मां के प्रेम, ममता और त्याग का सम्मान कर रही थी, उसी दिन एक मां अपनी दो मासूम बेटियों के साथ आग की लपटों में घिरकर हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। गैस सिलेंडर से रिसाव के बाद हुए भीषण अग्निकांड में मां और उसकी दोनों बेटियां जिंदा जल गईं। हादसा इतना भयावह था कि तीनों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिल सका। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर आंख नम दिखाई दे रही है।

यह दर्दनाक हादसा Rajasthan के ब्यावर जिले की रेलड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले काणेचा उदावतान गांव में हुआ। पुलिस के अनुसार एक दुकान के भीतर बने रसोईघर में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर मौजूद महिला और उसकी दोनों बेटियां कुछ समझ पातीं उससे पहले ही लपटों में घिर गईं।

मृतकों की पहचान 28 वर्षीय मनीषा और उनकी दो बेटियों 8 वर्षीय नविया तथा 5 वर्षीय पल्लवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह मनीषा रसोईघर में चाय बनाने गई थीं। प्रारंभिक जांच के अनुसार गैस सिलेंडर से पहले से रिसाव हो रहा था। जैसे ही उन्होंने गैस जलाने की कोशिश की, अचानक जोरदार आग भड़क उठी और पूरे रसोईघर में फैल गई।

हरिराम जाट ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि महिला और बच्चियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते पूरा रसोईघर आग की चपेट में आ गया। आसपास के लोगों ने धुआं और आग की लपटें उठती देख मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ताराचंद भट्ट के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल कर्मियों ने घंटों प्रयास के बाद आग बुझाई, लेकिन तब तक घर के अंदर रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। सबसे दर्दनाक दृश्य रसोईघर का था, जहां मां और दोनों बेटियों के शव बुरी तरह झुलस चुके थे। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे की तस्वीरें इतनी भयावह थीं कि उन्हें देखकर हर कोई सिहर उठा।

पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ब्यावर जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद गांव में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस हादसे को लेकर स्तब्ध हैं और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक ही परिवार की तीन जिंदगियों का इस तरह खत्म हो जाना पूरे गांव के लिए असहनीय सदमे जैसा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के कुछ ही मिनटों में घर से तेज धुआं निकलने लगा था। आसपास के लोग बाल्टियों और पानी के जरिए आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई अंदर नहीं जा सका। कई लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन लपटें और धुएं की तीव्रता के कारण बचाव कार्य मुश्किल हो गया।

इस हादसे ने एक बार फिर घरेलू गैस सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गैस सिलेंडर और पाइपलाइन की नियमित जांच बेहद जरूरी है। कई बार छोटे रिसाव समय पर पकड़ में नहीं आते और एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े हादसे का कारण बन जाती है। गर्मी के मौसम में ऐसी घटनाओं का खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि बंद कमरों में गैस तेजी से फैल सकती है।

स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गैस रिसाव आखिर किस कारण हुआ और क्या सिलेंडर या रेगुलेटर में कोई तकनीकी खराबी थी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या सुरक्षा मानकों में किसी तरह की लापरवाही हुई थी।

घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि मनीषा बेहद सरल स्वभाव की महिला थीं और अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करती थीं। मदर्स डे के दिन मां और बेटियों की एक साथ मौत ने हर किसी को भावुक कर दिया है। गांव की महिलाएं और बच्चे लगातार परिवार के घर पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं।

सामाजिक संगठनों ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। कई लोगों ने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सुरक्षा जागरूकता अभियान तेज करने की भी अपील की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

ब्यावर की यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उस असुरक्षा की भयावह तस्वीर है जो कभी-कभी घरों के भीतर छिपी रहती है। कुछ ही पलों में एक मां और उसकी दो मासूम बेटियों की जिंदगी खत्म हो गई और पीछे रह गया केवल मातम, दर्द और ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद कभी पूरी तरह नहीं मिल पाएगा।

टिकटों में महिलाओं की अनदेखी : राजनीतिक दलों की इच्छा पर सवाल उठ रहे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

देश में लोकसभा या विधानसभा चुनाव होने पर पर्याप्त संख्या में महिलाओं को टिकट देने की सच्ची इच्छाशक्ति की कमी का कारण क्या है? यह उल्लेखनीय है कि सभी दलों द्वारा टिकट दी गई महिलाओं की संख्या और चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में जीतने वाली महिलाओं की संख्या ही राजनीतिक दलों की महिलाओं की भागीदारी के प्रति उदासीनता पर सवाल उठाती है।

यह स्पष्ट है कि लगभग सभी दलों ने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। हालांकि, संसद में परिसीमन विधेयक के हाल ही में विफल होने के संदर्भ में, महिला आरक्षण का मुद्दा भी चुनावी मुद्दा बन गया है और भाजपा ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों पर आरोप लगाए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के दावों के बावजूद, भाजपा समेत सभी दलों में टिकट देने की इच्छाशक्ति का अभाव है। केवल औपचारिकता के लिए महिलाओं को टिकट देना उनकी सार्वजनिक प्रतिबद्धता को नहीं दर्शाता है।

वर्तमान में भाजपा केंद्र और अधिकांश राज्यों में सत्ता में है और खुद को महिला आरक्षण विधेयक का सबसे बड़ा समर्थक बताती है, तो फिर व्यवहार में इसे लागू क्यों नहीं कर रही है? यदि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में उसने महिलाओं को कम से कम 33% या इससे अधिक टिकट दिए होते, तो पूरा देश और विशेष रूप से महिलाएं पूरी तरह आश्वस्त हो जातीं कि भाजपा वास्तव में उन्हें प्रतिनिधित्व देना चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य से, ऐसा न होना बड़े शर्म की बात है।

दक्षिण अफ्रीका में मगरमच्छ के पेट में होटल मालिक के अवशेष मिलने से आक्रोश फैल गया है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हम अक्सर बातचीत में कहते हैं कि हम तुम्हें पूरा निगल जाएंगे। तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। हालांकि हम आमतौर पर यही सुनते हैं, दक्षिण अफ्रीका में गैब्रियल बतिस्ता नाम के 59 वर्षीय होटल मालिक कई दिनों से लापता थे। उनके होटल के पास कोमाटी नदी में बाढ़ आने के बाद से उन्हें कहीं नहीं देखा गया था।

लोगों को लगा कि वे बाढ़ में बह गए होंगे या पानी के बहाव के साथ कहीं दूर पहुँच गए होंगे। पुलिस ने गैब्रियल को खोजने के लिए आसमान-ज़मीन तक तलाशी ली, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार, कुछ दिनों बाद, बचाव दल को एक विशाल मगरमच्छ मिला। वह नदी के किनारे पड़ा हुआ था। उसका पेट फूला हुआ था और अंदर के भारी वजन के कारण वह बिना हिले-डुले वहीं पड़ा था।

उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। डराने के बावजूद वह हिला तक नहीं। उसका पेट फूला हुआ देखकर बचाव दल को शक हुआ कि मगरमच्छ ने शायद किसी पूरे आदमी को निगल लिया हो। इसी शक के आधार पर बचाव दल ने वन अधिकारियों से उसे मारने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद उन्होंने नदी किनारे हेलीकॉप्टर उतारा और मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर सुरक्षित स्थान पर ले गए।

मिशन 2027 की बिसात बिछाने में जुटी भाजपा, सामाजिक समीकरणों और क्षेत्रीय संतुलन से साधेगी सत्ता का रास्ता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होने लगी है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। सत्ता में लगातार मजबूत पकड़ बनाए रखने की कोशिश में जुटी भाजपा अब केवल संगठनात्मक विस्तार तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए व्यापक राजनीतिक संदेश देने की रणनीति पर काम कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के मंत्रिमंडल विस्तार और उससे जुड़े राजनीतिक संकेतों को इसी बड़ी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है।

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि भाजपा ने इस बार केवल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया, बल्कि इसके जरिए 2027 के चुनावी समीकरणों की झलक भी पेश कर दी। शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद सामने आई तस्वीरों में पार्टी ने जिस तरह विभिन्न जातीय और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के नेताओं को प्रमुखता दी, उसे भाजपा की सुनियोजित रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनाव में वह हर वर्ग और हर क्षेत्र को साथ लेकर मैदान में उतरेगी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। ऐसे में भाजपा भी यह भलीभांति समझती है कि सत्ता में वापसी का रास्ता सामाजिक संतुलन से होकर गुजरता है। यही वजह है कि हालिया राजनीतिक गतिविधियों में दलित, पिछड़ा और सवर्ण — तीनों वर्गों को समान रूप से प्रतिनिधित्व देने का प्रयास दिखाई दिया। पासवान, पांडेय, राजपूत, तोमर, पाल और चौधरी जैसे विभिन्न सामाजिक समूहों से आने वाले नेताओं की मौजूदगी को भाजपा के व्यापक सामाजिक संतुलन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा विशेष रूप से गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित वर्गों पर अपना फोकस लगातार मजबूत कर रही है। पिछले दो विधानसभा चुनावों में यही वर्ग भाजपा की बड़ी ताकत बनकर उभरा था और पार्टी अब इस सामाजिक गठजोड़ को और मजबूत करना चाहती है। मंत्रिमंडल और संगठन में ऐसे चेहरों को प्रमुखता देना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

विशेष रूप से अजीत सिंह पाल, भूपेंद्र चौधरी और कृष्णा पासवान जैसे नेताओं की मौजूदगी को गैर-यादव पिछड़े और गैर-जाटव दलित वर्गों तक भाजपा की पहुंच मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वहीं लोधी समाज से आने वाले कैलाश राजपूत को भी भाजपा के ओबीसी विस्तार अभियान का महत्वपूर्ण चेहरा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा समझती है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुंजी अब केवल पारंपरिक जातीय समीकरणों में नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करने में छिपी हुई है।

इसके साथ ही भाजपा अपने पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक को लेकर भी पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रही है। मनोज पांडेय और सोमेंद्र तोमर जैसे नेताओं को प्रमुखता देकर पार्टी ने यह संकेत दिया है कि विस्तार और संतुलन की रणनीति के बीच उसका पारंपरिक आधार उपेक्षित नहीं होगा। भाजपा की कोशिश साफ दिखाई दे रही है कि वह नए सामाजिक समूहों को जोड़ने के साथ-साथ अपने पुराने समर्थक वर्ग को भी पूरी मजबूती से साथ बनाए रखे।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा की रणनीति केवल जातीय संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय समीकरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य यूपी — तीनों क्षेत्रों से नेताओं की भागीदारी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि पार्टी पूरे प्रदेश में संतुलित राजनीतिक पकड़ बनाए रखना चाहती है। खासकर पूर्वांचल को लेकर भाजपा अतिरिक्त सतर्क दिखाई दे रही है क्योंकि यह क्षेत्र विधानसभा की बड़ी संख्या में सीटों के कारण सत्ता की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और सामाजिक समीकरणों के चलते पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक परिस्थितियां बदली थीं। ऐसे में भाजपा अब वहां भी नए सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश में जुटी दिखाई दे रही है। वहीं मध्य यूपी में परंपरागत राजनीतिक मुकाबले को देखते हुए संगठनात्मक मजबूती और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी जा रही है।

राजनीतिक विश्लेषक सियाराम पांडेय का मानना है कि हालिया आयोजन भाजपा के लिए केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह एक प्रकार का "टीम शोकेस" था। उनके अनुसार पार्टी ने इस मंच के जरिए अपनी सामाजिक और क्षेत्रीय ताकत को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य केवल विपक्ष को राजनीतिक संदेश देना नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना भी है कि भाजपा पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है।

विश्लेषकों के अनुसार भाजपा यह भी समझती है कि 2027 का चुनाव केवल विकास कार्यों या सरकार के प्रदर्शन के आधार पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि सामाजिक गठजोड़, स्थानीय नेतृत्व और संगठनात्मक एकजुटता भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यही कारण है कि पार्टी अभी से विभिन्न सामाजिक समूहों और क्षेत्रों के नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।

दूसरी ओर विपक्षी दल भी भाजपा की इस रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां भी अपने-अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटी हैं। ऐसे में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरणों की चर्चा और तेज होने की संभावना है।